

विचार बिन्दु

घर का मोह कायरता का दूसरा नाम है। -अज्ञात

आरक्षण के चक्रव्यूह में देश कब तक फंसा रहेगा।

सीजेआईडीवाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से दिनांक 01.08.2024 का निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 6 न्यायाधीश निर्णय में एक मत थे, उनमें सीजेआईडीवाई चन्द्रचूड़, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मिथल थे और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी का निर्णय अलग था। इस निर्णय में जो निर्णय 6 न्यायाधीशों का है उन्हींने यह माना है कि राज्यों को एएससी एसटी की बंधन केंटेगरी तय करने का अधिकार है। पीठ के चार जजों ने एएससी में भी क्रीमीलेयर लागू करने की बात कही है। वस्तुतः जस्टिस बी आर गवई ने अपने फैसले में उक्त बात लिखी है और शेष तीन जजों ने जिनमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मिथल व जस्टिस सतीश चंद्र व जस्टिस गवई के निर्णय से सहमति अभिव्यक्ति की है। जस्टिस गवई ने अपने निर्णय में कहा है कि राज्यों को ओबीसी की भांति एएससी एसटी (अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति) क्रीमीलेयर की पहिचान करनी चाहिये। इसका अर्थ है आरक्षण का फायदा पा चुके व्यक्तियों को बाहर कर, जो अति वंचित रह गये हैं, उन्हें अवसर दिया जाना चाहिये। जस्टिस गवई से भिन्न इसी बात को जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा है कि अगर परिवार में किसी भी पीढ़ी ने रिजर्वेशन (आरक्षण) का लाभ पा लिया है तो दूसरी पीढ़ी को यह लाभ नहीं मिलना चाहिये।

यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि सुप्रीम कोर्ट की उक्त संविधान पीठ (सात न्यायाधीश) के समक्ष यह प्रश्न निर्णित किया जाना था कि क्या राज्यों की एएससी-एसटी की सब केंटेगरी बनाने का अधिकार प्राप्त है? यह भी उल्लेखनीय तथ्य था कि कोटा तय करते समय हिस्सेदारी का पूरा डेटा होना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि सरकार के पास पर्याप्त डेटा है तो उस केंटेगरी (श्रेणी) बनाई जा सकती है। इस प्रकार अन्तिम छोर पर जो गरीब है, उसे भी न्याय मिल सकेगा। इस प्रक्रिया से यानी सब कोटा की पहिचान से सबसे ज्यादा लाभ पिछड़ी जातियों को प्राप्त होगा।

उपरोक्त जो विश्लेषण किया गया है, इसके माध्यम से जो लिखा है वह यह स्पष्ट करता है कि संविधान पीठ के समक्ष जो प्रश्न था वह केवल इतना ही था कि क्या 'राज्यों को एएससी-एसटी की सब केंटेगरी तय करने का अधिकार है'। यदि पीठ सब केंटेगरी के राज्य के अधिकार को मान लेती है तो इससे यह प्रभाव होगा कि बड़ी पीठ (सात जजों की पीठ) ने पूर्ववर्ती 5 जजों की संविधान पीठ के निर्णय को जो उसने ई वी चिन्नेया के मामले में सन् 2004 में दिया था, उसे निरस्त कर दिया है। 2004 के इस निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने यह तय किया था कि 'एएससी-एसटी के आरक्षण के लिये सब केंटेगरी नहीं बनाई जा सकती'। 1 अगस्त 2024 के निर्णय का प्रभाव Prospective होगा।

प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या 2024 के निर्णय से देश के दलितों को अपरिमित हानि हुई और यह नया निर्णय किया जाना अपरिहार्य था, देश के दलितों के हित में किया जाना अति आवश्यक था।

दिनांक 01 अगस्त, 2024 के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राज्यों के पास अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण का संवैधानिक अधिकार है, इससे उस जाति के लोगों को आरक्षण मिलेगा तो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा था वर्गीकरण का आधार पिछड़ेपन और सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व व मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर करना चाहिये न कि किसी राजनीतिक लाभ प्राप्ति हेतु।

दिनांक 01 अगस्त, 2024 के निर्णय के बाद इस पर राजनीतिक पार्टियों व राजनीतिक विद्वानों आदि को अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलीं।

एएससी-एसटी वर्ग के सांसदों ने प्रधानमंत्री से कहा है कि उनके समाज को आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है अपितु उसका आधार छुआछूत, भेदभाव, सामाजिक सुधार पर है, फलस्वरूप यह विषय क्रीमीलेयर का नहीं है। भाजपा के दलित व आदिवासी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर मांग की है कि क्रीमीलेयर को लागू न करें। मोदी ने उनकी बात मान ली है। केबीनट ने भी उस पर स्वीकृति की मोहर लगा दी। केन्द्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एएससी-एसटी में कोई क्रीमीलेयर प्रवधान नहीं है।

ऐसा कहा गया है कि एएससी-एसटी में आरक्षण में वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आरएसएस को भी पसंद आया है।

बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब आरक्षण को समाप्त करना है और उसे सामान्य वर्ग को देना है। मायावती आरक्षण में किसी भी तरह के वर्गीकरण के विरुद्ध हैं।

इन्द्रा साहनी के बाद आरक्षण को लेकर कई संविधान पीठों के निर्णय हो चुके हैं, किन्तु आरक्षण का चक्रव्यूह अभी तक टूट नहीं पाया है। प्रत्येक निर्णय के बाद नया विवाद खड़ा हो जाता है। 2024 के निर्णय के बाद कई नये विवाद उत्पन्न होंगे इसमें कोई शंका नहीं है।

डा. विजय सोनकर शास्त्री जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के चेयरमैन रहे हैं और सांसद भी रहे हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के फैसले को ऐतिहासिक कहा है। इससे आरक्षण से वंचित रही जनजाति को भी लाभ मिलेगा। उनका कहना है कि देश में एएससी व एसटी की आबादी 22.5 प्रतिशत है, यदि यह वर्ग विकास में पीछे रह गया तो देश पिछड़ जायेगा। डा. शास्त्री ने कहा दलितों की कुल 1208 जातियाँ और 10 हजार उपजातियाँ हैं, इस स्थिति में वर्गीकरण करना चुनौती पूर्ण है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप एएससी-एसटी श्रेणियों के मध्य एक राजनीतिक लड़ाई जन्म लेगी।

राजेन्द्र भानावत पूर्व आईएसएस अधिकारी ने राष्ट्रदूत के अतिथि सम्पादकीय में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ऐतिहासिक क्रान्तिकारी कहा है। भानावत जी का मानना है कि यह निर्णय धरातल पर लागू नहीं हो पायेगा।

दिनांक 1 अगस्त, 2024 के निर्णय के दो भाग स्पष्ट हैं। एक भाग में सीजेआई चन्द्रचूड़ का आदेश है जो उन्होंने जस्टिस बेला त्रिवेदी के अलावा शेष जजों और अपनी ओर से लिखा है, जिसका सार है 'कोटे में कोटा' हो सकता है, राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वे एएससी-एसटी वर्ग में शामिल समुदायों के लिये आरक्षित कोटे में से पिछड़ेपन के आधार पर कोटा तय करें। वहीं जस्टिस गवई ने माना है कि क्रीमीलेयर को एएससी-एसटी पर भी लागू करें। वर्तमान में ओबीसी आरक्षण में वार्षिक आठ लाख रुपये कमाने वाले क्रीमीलेयर में आते हैं।

अधिकार लोग यह मानते हैं कि ईवी चिन्नेया बनाम आन्ध्रप्रदेश के केस का 2004 का निर्णय 01.08.2024 के निर्णय से Over Rule हो गया है। 2004 के निर्णय में 5 जजों की पीठ ने यह माना था कि आरक्षित कोटे में सब केंटेगरी नहीं हो सकती। क्रीमीलेयर के विषय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। क्रीमीलेयर का विवाद न तो 2004 के निर्णय का विषय था और न ही 2024 के निर्णय के विषय का ही भाग था। यह विषय जस्टिस गवई के निर्णय का भाग है। जस्टिस गवई का निर्णय जिसका समर्थन जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस सतीश चंद्र और जस्टिस विक्रम नाथ ने किया है। चूँकि क्रीमीलेयर का विषय रफरेंस का विषय नहीं है अतः 2004 के निर्णय को वह निरस्त नहीं कर सकता।

सन् 2004 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानता है कि आरक्षण को केंटेगरी में उप केंटेगरी नहीं हो सकती और 01 अगस्त 2024 का निर्णय घोषणा करता है कि केंटेगरी में सब केंटेगरी हो सकती। कुछ विद्वान कहते हैं कि निर्णय से भी यह स्पष्ट नहीं है कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। यह भी कहा जा सकता है कि पर्याप्त आंकड़ों के तथा विश्लेषण व विवेचना के उपवर्गीकरण संभव ही नहीं है।

कोरिस अध्यक्ष खडके का आरोप है कि भाजपा क्रीमीलेयर के आधार पर आरक्षण की छतम करना चाहती है जबकि आरक्षण उस समय तक चालू रहना चाहिये जब तक छुआछूत का पाप समाप्त नहीं हो जाता। खडके ने पीएम मोदी के उस कथन का घोर विरोध किया है जब पीएम ने कहा था कि संविधान में क्रीमीलेयर का कोई प्रावधान नहीं है और सरकार क्रीमीलेयर लागू नहीं करेगी। खडके का कहना है कि भाजपा/एनडीए को अपने कथन के अनुसार संसद में अधिनियम लाकर ही ऐसा करना चाहिये।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 01.08.2024 के निर्णय के अनुसार कोटे में कोटा हो सकता है किन्तु उसका क्रियान्वयन कठिन है तथा पर्याप्त आंकड़ों व विश्लेषण व विवेचना के यह सम्भव नहीं है। जहाँ तक क्रीमीलेयर के आधार पर आरक्षण का प्रश्न है, और दिनांक 01.08.2024 के निर्णय से इसका संबंध है निम्नलिखित कुछ आपत्ति विचारणीय हैं:-

- 1) 2004 के सुप्रीम कोर्ट का कोई संबंध क्रीमीलेयर के विषय से नहीं है और न उस रफरेंस से है जिसके Determination के लिये केस को 7 जजों की पीठ को भेजा गया था।
- 2) दिनांक 01.08.2024 का मूल निर्णय वह है, जो निर्णय सीजेआई चन्द्रचूड़ ने अपने 5 अन्य जजों के साथ दिया है, जिसका सार है कोटे में कोटा हो सकता है और उप वर्गीकरण का अधिकार राज्य सरकार का है।
- 3) जस्टिस गवई के निर्णय में क्रीमीलेयर का उल्लेख है। इस निर्णय के अनुसार यह माना गया है कि एएससी व एसटी में भी ओबीसी की भांति क्रीमीलेयर के सिद्धान्त को लागू किया जाना चाहिये। हाँ जस्टिस गवई का समर्थन अन्य तीन न्यायाधीशों ने भी किया है, किन्तु यह अलग निर्णय है और रफरेंस की सीमा में नहीं है अतः इसका कोई संबंध 2004 के निर्णय को Over Rule करने से नहीं है।
- 4) पीएम मोदी व उनकी सरकार ने एएससी-एसटी में क्रीमीलेयर के सुझाव को स्वीकार नहीं किया है। स्वयं पीएम मोदी ने दलित व आदिवासी सांसदों की मांग को स्वीकार किया है। यह मोदी का वायदा है अतः इस विषय पर चर्चा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्गीकरण का आधार पिछड़ेपन और सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर करना होगा, न कि राजनीतिक लाभ के आधार पर।

इन्द्रा साहनी के बाद आरक्षण को लेकर कई संविधान पीठों के निर्णय हो चुके हैं, किन्तु आरक्षण का चक्रव्यूह अभी तक टूट नहीं पाया है। प्रत्येक निर्णय के बाद नया विवाद खड़ा हो जाता है। 2024 के निर्णय के बाद कई नये विवाद उत्पन्न होंगे इसमें कोई शंका नहीं है। संविधान पीठों के गठन पर अंकुश लगाना आवश्यक प्रतीत होता है। सन् 1994 के बाद 2192 केसेज का निस्तारण हो चुका है, फिर भी 50 केस अभी भी निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। लेखक का अपना विचार है कि संविधान पीठ के निर्णय को उसी समय Over Rule करना चाहिये जब निर्णय के कारण जनता के अधिकारों का हान हो रहा हो। विचारों की भिन्नता मात्र निर्णय को पलटने का कारण नहीं होना चाहिये। सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



प्रो. अशोक कुमार

रोजगार के लिए युवाओं के कौशल विकास के नाम पर किए जा रहे नित नए दावों के बीच हकीकत यह है कि विभिन्न संस्थानों में पिछले कई वर्षों से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक तक नहीं है। विभिन्न संस्थानों ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार,

कौशल विकास विभाग के संबंधित अधिकारियों से सामने कई बार अपनी परेशानी रख चुके हैं। शिक्षकों की मांग करते हुए पत्र लिख चुके हैं लेकिन हमें जवाब दे दिया जाता है कि जल्दी ही भर्ती की जाएगी। किसी तरह घंटे के आधार पर शिक्षकों को पढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है जिससे विद्यार्थी थोड़ा बहुत कुछ सीख पाए। इस शिक्षकों को पैसे भी संस्थान अपनी ओर से दे रहा है। दाखिले ऑनलाइन किए जा रहे हैं और बाद में विद्यार्थी पढ़ने आते हैं तो उन्हें परेशानी समझ में आती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सिखाने-पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सभी तरह की साधन सामग्री उपलब्ध नहीं है और जहाँ पर साधन सामग्री उपलब्ध है लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए यह सिखाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। न प्रशासन

कई वर्षों से कह रहा है कि विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन के द्वारा यह कदम कब उठाए जाएंगे और जो विद्यार्थी इन विषयों में बिना पढ़े ग्रेड प्राप्त कर चुके हैं, क्या वह रोजगार के लिए उपयुक्त होंगे?

स्नातक स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना एक सराहनीय प्रयास है, लेकिन शिक्षकों के अभाव में इन कार्यक्रमों को चलाना कई कारणों से वित्तात्मक है:-

चिंता के कारण : विषय विशेषज्ञ शिक्षक न होने से छात्रों को गहराई से समझ नहीं मिल पाती है। कई कौशल विकास कार्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसे बिना अनुभवी शिक्षकों के करना मुश्किल होता है। शिक्षकों के अभाव में कार्यक्रमों की शैक्षणिक गुणवत्ता

प्रभावित होती है। शिक्षकों के अभाव में छात्रों का रुझान इन कार्यक्रमों से कम हो सकता है। बिना शिक्षकों के कार्यक्रम को सफलता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है।

संभावित समाधान : विषय विशेषज्ञ अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऑनलाइन मोड में विषय विशेषज्ञों द्वारा वीडियो लेक्चर और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। छात्रों को एक-दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। मौजूदा शिक्षकों को कौशल विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।

निष्कर्ष:- स्नातक स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन एक सराहनीय प्रयास है, लेकिन बिना शिक्षकों के इन कार्यक्रमों को चलाना उचित नहीं है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी पक्षों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।

-प्रो. अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय

किशनगढ़ बास से खैरथल तक 10 किलोमीटर की निकाली तिरंगा यात्रा

किशनगढ़ बास/खैरथल, (निसं)। आजादी के अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान के तहत आमजन में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के उद्देश्य से किशनगढ़ बास के बंबोरा घाटा हनुमान मंदिर से खैरथल तक 10 किलोमीटर की तिरंगा बाइक यात्रा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जल वायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, पूर्व विधायक रामहेत यादव सहित भाजपा नेताओं की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई। वहीं केंद्रीय मंत्री ने खैरथल में आयोजित विभाजन विधौषिका प्रदर्शनी कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

किशनगढ़ बास के घाटा बंबोरा हनुमान मंदिर से खैरथल के लिए प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हनुमान मंदिर में श्री भगवान राम और हनुमान जी के दर्शन कर ढोक लगाई और पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश व जिले की खुशहाली की कामना की। इसके बाद मंत्री ने तिरंगा लहराकर यात्रा की शुरुआत की और तिरंगा यात्रा में शामिल होकर राष्ट्रीय एकता व देश भक्ति का संदेश दिया।

तिरंगा यात्रा रथ में सवार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ पूर्व विधायक रामहेत सतीश यादव, मंत्री हेमसिंह भड़ाना, जिला प्रमुख बलबीर डिल्लेर, पालिका अध्यक्ष तारामणि सतीश सैतवाल, हरीश रोधा सहित भाजपा नेताओं का किशनगढ़ बास अभिभाषक संघ अध्यक्ष अजीत राव पूर्व अध्यक्ष अमित गौड़ के नेतृत्व में अधिवक्ताओं की ओर से यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा रथ पर सवार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित नेताओं व बाइक पर चल



खैरथल में तिरंगा यात्रा रथ में सवार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ पूर्व विधायक रामहेत सतीश यादव व अन्य थे।

रहे कार्यकर्ताओं के हाथों में लहर लहर लहराता हुआ तिरंगा व भारत माता की जय घोष व देश भक्ति के गीतों ने लोगों के दिलों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को जागृत किया।

खैरथल तिरंगा यात्रा पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित भाजपा नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री व पूर्व विधायक रामहेत यादव सहित भाजपा नेताओं ने विभाजन विधौषिका प्रदर्शनी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विभाजन विधौषिका प्रदर्शनी विभाजन के इतिहास को समझने और इससे सीखने का माध्यम है। इसमें युवा पीढ़ी को विभाजन काल की

प्रतिकूलताओं की जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि असंख्य देश भक्तों के सर्वोच्च बलिदान के बाद हमें आजादी मिली हमें ऐसे महान देशभक्तों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना बहुत जरूरी है। यादव ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान आमजन की सहभागिता के साथ प्रदेशभर में आयोजित किया जा रहा है जो प्रगतिशील भारत, देश की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की ओर से की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पहल

है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों पर तिरंगा झण्डा लगाकर राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस को हार्थोल्लास के साथ मनाने के लिए कहा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने खैरथल को ग्रेटर खैरथल बनाने की बात कही साथ ही केंद्रीय फंड से खैरथल से शेखपुर अहीर सड़क निर्माण जो की खैरथल से आरंभ होकर बवेरी कलां, माचरीली, दौलतपुर, बीबीरानी, जलालपुर, जोड़िया, भिनोलिया, शेखपुर अहीर तक 41 किलोमीटर की सड़क 61.5 करोड़ रुपए तथा शेरपुर से गेलपुर सड़क निर्माण जो की शेरपुर से आरंभ होकर जोड़िया, भोकर, गेलपुर तक 10 किलोमीटर की सड़क

जान जोखिम में डालकर कल्याण भक्त कर रहे यात्रा

मालपुरा, (निसं)। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल डिगगी कल्याणजी के दरवार में चल रहे 59 वें लक्ष्मी मेले के चौथे दिन बुधवार को भारी अव्यवस्थाओं के चलते यात्रियों को जान जोखिम में डालकर यात्रा बसों में सफर करने की तस्वीरें सामने आईं।

लक्ष्मी मेले से पूर्व जिला कलेक्टर सोम्या झां की अध्यक्षता में जिला व उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों की ली गई बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को मेले की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखे जाने के

सख्त निर्देश दिये थे। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों ने मेले में आने वाले यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा के सभी इंतोजमात किये जाने की जानकारी दे जिला कलेक्टर को मेले के सफल आयोजन के लिए आश्चस्त किया था। लेकिन मेले के दौरान भारी अव्यवस्थाओं के चलते यात्रियों को जानजोखिम में डालकर यात्रा करने व दर्शनों के पश्चात गंतव्य स्थान पर जाने के लिए भी बसों की छतों पर बैठकर तो बसों की छिड़की व फाटक पर लटककर यात्रा करने पर विवश होते देखा गया। परिवहन विभाग के

अधिकारियों ने ऑवरलोडिंग वाहनों पर सख्त कार्यवाही के दावे किये गये थे। उनकी भी पील खुलकर सामने आई। वैशाली व टोंका डिपो के अधिकारियों ने पांच दिवसीय मेले के दौरान 100 अतिरिक्त बसें लगाने की जानकारी दी थी लेकिन जमीनी स्तर पर आधी ही बसें यात्री भार उठाते देखीं गईं।

बसों के अभाव में मजबूर यात्री बसों की छतों पर बैठकर तो बसों में भेड़ बकरी की तरह दूंस-दूंस कर व लटककर जान जोखिम में डाल सफर

करने के लिए विवश देखे गये। जयपुर भीलवाड़ा व दूदु छाण स्टेट हाईवे सहित डिगगी चौसला व अन्य मार्गों पर सड़क के दोनों ओर जंगल सफाई नहीं होने व जगह-जगह गन्दगी के ढेर लगे होने से पैदल यात्रियों को बीच सड़क पर बैठकर विश्राम करते देखा गया। मेले में बेरिकेटिंग तो लगाई गई लेकिन तैनाद पुलिस के अधिकारी व जवान पैदल यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा को नजर अंदाज कर प्रतिबंधित मार्ग में दुर्घटना का कारण। मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी इस बार मेले में यात्रीयों की सुविधा व सुरक्षा के लिए माकुल इंतोजमात नहीं किये जाने से कल्याण भक्तों में ट्रस्ट के प्रति भी गहरा आक्रोश देखा गया।

राशिफल गुरुवार 15 अगस्त, 2024



पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत् 2081, ज्येष्ठ नक्षत्र दिन 12:53 तक, वैधुति योगदिन 2:58 तक, गर करण दिन 10:27 तक, चन्द्रमा दिन 12:53 से धनु राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-वृष, बुध-सिंह, गुरु-वृष, शुक-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में। आज रविवोग दिन 12:53 तक है। आज भद्रा रात्रि 10:03 से आरम्भ होगी। आज वैधुति पुण्य है और पारसी नव वर्ष प्रारम्भ होगा। आज नवरोज है। श्रेष्ठ चौधड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:39 तक, चर 10:54 से 12:31 तक, लाभ-अमृत 12:31 से 3:46 तक, शुभ 5:23 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:02, सूर्यास्त 7:00

मेघ	अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बन्ते कार्य विगड़ सकते हैं। आज मध्यह्न पश्चात अटके हुए कार्य बन्ने लगेगे।
वृष	परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उसबव जैसा सामंल हो सकेते हैं। दिन के मध्यह्न पश्चात अटके हुए कार्य बन्ने लगेगे।
मिथुन	स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अटके हुए कार्य बन्ने लगेगे। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। दिन के मध्यह्न पश्चात परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।
कर्क	परिवार में शुभ-मौलिक कार्य सम्पन्न हो सकेते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच-विचार हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल उंचा रहेगा।
सिंह	घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी।
कन्या	परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। नये-पुराने मित्रों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। परिवार में धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।
तुला	आर्थिक कार्यों से अटके हुए कार्य बन्ने लगेगे। संपातित खेत से धन प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्य शीघ्रता/सुगमता से बन्ने लगेगे। आम मित्र/रिश्तेदारों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।
धनु	घर-परिवार कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में अस्तोष बना रहेगा। घर-पहुँचस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। दिन के मध्यह्न पश्चात परेशानियों से राहत मिलेगी।
मकर	आर्थिक/वित्तिय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। दिन के मध्यह्न पश्चात अगल कार्यों में समय खराब होगा। अनावश्यक धन खर्च होगा।
कुंभ	व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बन्ने लगेगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। दिन के मध्यह्न पश्चात परिवार में शुभ-मौलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।
मीन	नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बन्ने लगेगे। दिन के मध्यह्न पश्चात महत्वपूर्ण कार्यों के संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।